>

Title: Need to formulate a comprehensive scheme for development of agriculture sector.

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): भारत कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। लेकिन कृषि में ढांचागत सुधारों को लेकर कुछ नहीं हो रहा है। कृषि विकास को निर्धारित करने वाले सभी मोर्चों पर हम विफल हो रहे हैं। किसान खाद एवं कीटनाशक दवाओं में हो रही लगातार मूल्य वृद्धि से बोझ के तले दबता चला जा रहा है। सिंचाई योजनाओं पर हजारों करोड़ रूपये खर्च करने के बाद भी देश का मात्र 40 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित हो पाया है। देश के अधिकांश राज्यों में कृषि अभी भी ज्यादातर मानसून पर निर्भर है। उर्वरक नीति पर भी ढुलमुल दृष्टिकोण अपनाया जाता है। कृषि ऋणों पर छूट का लाभ ज्यादातर बड़े कृषकों को ही मिल जाता है। क्योंकि गांवों में अभी भी एक दो एकड़ कृषि भूमि के छोटे किसान स्थानीय सेठों पर निर्भर रहते हैं। भारी अनुसंधान तथा सरकारी सहायता के बाद भी बीजों के अनुसंधान में हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरफ ही देखते हैं। भंडारण के अभाव में हर वर्ष लाखों टन अनाज सड़ जाता है। कृषि विकास की गति धीमी होने के कारण क्षेत्र से गांव के युवकों का मोह भंग हो रहा है तथा वह शहरों की ओर अन्य छोटे मोटे कामों की तरफ भाग रहा है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गांवों में बुनियादी सुविधायें उपलब्ध करने तथा कृषिके संबंध में समग्र नीति बनाकर ग्रामीण युवकों को कृषि कार्य में जोड़ने का कार्य करें ताकि गांव भी बचे और खेती भी बचे।